

मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु संयोजन योजनान्तर्गत (एस०सी०एस०पी०)

प्रेषक.

संख्या:- [405 / 111(2) / 11-08(प्रा0आ0) / 2010टी०सी०-1

महिमा, अनु सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांकः 22 मार्च, 2011

मुख्य मंत्री ग्रामीण सेतु संयोजन योजना (एस०सी०एस०पी०) के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट में गाडगांव लग्गा मैचाली में 12 मी0 पैदल पुलिया के निर्माण की प्रशासकीय, वित्तीय एवं व्यय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषय:-

A Comment of the Comm

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु संयोजन योजना (एस०सी०एस०पी०) के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता कु०क्षे०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट में गाडगांव लग्गा मैचाली में 12 मी0 पैदल पुलिया के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यो यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू—अधिग्रहण, यूटीलिटी शिपिटंग, मृदा परीक्षण, भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि मदों, के लिये टी०ए०सी० वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 2.82 लाख (₹ दो लाख बयासी हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) के व्यय की, महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (ii)— उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:-1764/।।।(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही पैदल सेतु के निर्माण का कार्य
- (iii)— आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोद्ति दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iv)— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित
- (vi)— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vii)— स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स—2008 एवं उक्त के विषय में समय—समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के

(viii)— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:— 2047 / XIV—219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix)— स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0— 30—लेखाषीर्शक—5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय —04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-02 मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु संयोजन योजना-00-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।
- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 324(1)/XXVII/(2)/2010 दि0: 21 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। भवदीय,

(महिमा) अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :--

- महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून। 1.
- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल। 2.

जिलाधिकारी पिथौरागढ।

मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि. अल्मोड़ा। 4.

मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, जनपद पिथौरागढ़ / देहरादून। 5.

निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।

- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो०नि०वि० पिथौरागढ़। 8.
- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन । 9.

गार्ड बुक। 10.

आूज्ञा से, (महिमा) अनु सचिव